LOK SABHA

Wednesday, November 15, 1967/
Kartika 24, 1889 (*Saka*)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. SPEAKER : Shri Viswambharan.

SHRI P. VISWAMBHARAN : Question No. 61.

SHRI D. N. PATODIA : I suggest that Question No. 65, which is on the same subject, may be taken up along with this.

MR. SPEAKER : All right. Question No. 70 may also be taken up.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Sir, question No. 70 is on a slightly different subject.

MR. SPEAKER : All right. Only 65 need be taken up along with 61.

ADMINISTRATIVE REFORMS COMMISSION

*61. SHRI P. VISWAMBHARAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) when the Administrative Reforms Commission was set up ; and

(b) the time limit stipulated for the submission of the final report of the Commission and when it is expected to be submitted ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) 5th January, 1966.

(b) No time limit was stipulated in the terms of reference, which only required the Commission to make its report to the Government of India as soon as practicable. The Commission expects most of the study teams and working groups appointed by it to submit their reports in about 3 months. The Commission may then take some time to consider these reports and finally report to the Government on all the subjects under study.

प्रशासनिक सुधार आयोग

†

65. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री मणीभाई जे० पटेल :
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग का पूरा प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) क्या आयोग के कुछ सुझाओं को क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ग) आयोग द्वारा अब तक की गई सिफारिशों के बारे में अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग). सदन के सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) श्रीमान्, नहीं ।

(ख) और (ग). आयोग द्वारा सरकार को अब तक तीन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं—पहला नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्या पर, दूसरा आयोजना के तंत्र पर व तीसरा राजकीय क्षेत्र उपक्रमों पर।

इसकी नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्या सम्बन्धी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। उन पर निर्णय, जितनी जल्दी हो सका, लिया जायेगा।

जहां तक आयोग की आयोजना के तंत्र पर सिफारिशों का प्रश्न है, प्रधान मन्त्री द्वारा 17 जुलाई, 1967 को लोक सभा में दिये गये विवरण की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता